forcibly seized by the Bank from some creditors who did not pay the instalments; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) Reserve Bank of India have reported that in the absence of specific complaints they had no occasion to investigate this matter.

(c) Does not arise.

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

2801. **श्री विनोद शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक नया आयोग गठित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि नवम्बर, 1991 में श्री नरसिम्हम की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन के आधार पर सरकार द्वारा बैंकिंग प्रणाली में अब तक क्या सुधार किए गए हैं ;

(घ) सरकार द्वारा किन-किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है परंतु उन्हें अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ; और

(ङ) बैंकिंग प्रणाली के किन-किन पहलुओं को सुधारने के लिए उन्हें प्रस्तावित नए आयोग को सौंपे जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) वित्तीय प्रणाली अध्यक्ष एम नरसिंहम पर समिति का गठन अगस्त 1991 में किया गया था और उसकी रिपोर्ट सरकार को नवंबर 1991 में प्राप्त हुई थी । समिति की सिफारिशों के अनुक्रम में किए गए सुधारात्मक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: एस.एल.आर और सी.आर.आर. में कमी, ब्याज दर संरचना का सरलीकरण, पूंजी पर्याप्तता के संबंध में मानकों का निर्धारण, आय की पहचान और प्रावधान संबंधी अपेक्षायें, अधिक सुस्पष्टता के लिए तुलन पत्र और लाभ तथा हानि फार्मेटों का संशोधन, शाखा लाइसेंसिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देशों में संशोधन, पूंजी बाजार को उदार करने के उपाय, एस.ई.बी.आई को सांविधिक शक्तियां प्रदान करना, विभिन्न म्यूचुअल फण्डों से कर में रियायतों के मामले में एक समान व्यवहार करना आदि । समिति की अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

(ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

Recovery of agricultural loans

2802. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Governments are being asked to apply Revenue Recovery Act for recovery of Agricultural loans advanced by Nationalised Banks; and

(b) if so, what is the response of various State Governments thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) An Expert Group on State Enactment having a bearing on commercial banks' lending to agriculture (Talwar Committee) had recommended enactment on legislation by various State Governments and Union Territories on the lines of 'Model Bill' evolved by them for the purpose. In pursuance of the above recommendation, State Governments were advised to enact legislation for speedy recovery of agricultural advances of commercial banks. The following 16 States have already enacted the legislation on the subject: (1) Assam, (2) Bihar, (3) Gujarat (4) Haryana, (5) Himachal Pradesh, (6) Karnataka, (7) Madhya Pradesh, (8) Maharash-

tra, (9) Manipur, (10) Meghalaya, (11) Orissa, (12) Punjab, (13) Rajasthan, (14) Tripura, (15) Uttar Pradesh, and (16) West Bengal.

बजटपूर्व संगोष्ठी के लिए हर्षद मेहता को आमंत्रण

2803. **डा० अबरार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने इस वर्ष आयोजित बजट-पूर्व सरकारी संगोष्ठी में भाग लेने के लिए हर्षद मेहता को आमंत्रित किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने उसे आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की और साथ ही इस प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार उक्त संगोष्ठी में मेहता को आमंत्रित किए जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की परिसंपत्तियों और आचरण की जांच करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) जी नहीं । हां, योजना आयोग के एक सदस्य के सुझाव पर वित्त सचिव ने श्री हर्षद मेहता को मुलाकात करने का समय दिया था । श्री मेहता ने इस मुलाकात में देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए थे । बजट संबंधी किसी मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई थी ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Auditors of banks involved in securities scam

2804. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the names of the auditors of each of the nationalised banks reported to be involved in the recent securities scam for the last three years;

(b) whether audit reports point out irregularities in this respect; and

(c) what action is contemplated against the alleged negligence of the auditors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) The names of statutory central auditors of State Bank of India, State Bank of Saurashtra and UCO Bank (among nationalised banks) which figure in the interim reports of Janakiraman Committee set up by Reserve Bank of India to enquire into irregular securities transactions for the years 1989-90, 1990-91 and 1991-92 are given in the Statement attached. (See below)

(b) The auditors of State Bank of India and State Bank of Saurashtra had adversely commented on certain transactions in securities whereas the auditors of UCO Bank have mentioned that it is not possible to comment pending completion of investigation.

(c) Action, if any, against the auditors can be considered after it is established that there has been any negligence on their part.

Statement

LIST OF AUDITORS

(I) STATE BANK OF INDIA
1989-90:

1. M/s. Ramanlal G. Shah and Co., Ahmedabad (Ahmedabad Circle).
2. M/s. Ratan S. Mama and Co., Bombay (Bombay Circle).
3. M/s. Lovelock and Lewes, Calcutta (Bengal Circle).
4. M/s. Doogar and Associates, New Delhi (Bhopal Circle).
5. M/s. Tej Rwaj and Pal, Bhubaneshwar (Bhubaneshwar Circle).
6. M/s. B. K. Ramadhyani and Co., Bangalore (Bangalore Circle).